भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1686
उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

5जी सेवाओं का प्रभाव

1686. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सेवा और संचयी आर्थिक प्रभाव दोनों के संदर्भ में 5जी सेवाओं के प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जीडीपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और
(ग) इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शिता के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव और शहरी परिदृश्य में प्रौद्योगिकी के परिवर्तन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) भारत में 5जी सेवाओं का शुभआरंभ 1 अक्तूबर, 2022 को हुआ था। 1 दिसंबर 2023 तक देश के 738 जिलों को शामिल करते हुए 3.99 लाख 5जी बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) रोलआउट किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 5जी बीटीएस लगाए जा रहे हैं। मोबाइल डाउनलोड स्पीड में बड़ा सुधार हुआ है। अक्तूबर 2023 में भारत 75.86 एमबीपीएस की मीडियन डाउनलोड स्पीड के साथ ओकला द्वारा स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 28वें स्थान पर रहा। मार्च 2014 में डाउनलोड स्पीड 1.30 एमबीपीएस थी। 5जी के रोलआउट के लिए प्रतिबद्ध कुल निवेश 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है।

भारत के डिजिटल परिदृश्य में काफी परिवर्तन और विकास हुआ है। भारत सभी के लिए डिजिटल सेवाएं, डिजिटल अभिगम, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तीकरण सुनिश्चित करते हुए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने के पथ पर अग्रसर है। अभी तक की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

I. आधार

- आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान कार्यक्रम है।
- आधार फिंगरप्रिंट आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण, आईरिस-आधारित प्रमाणीकरण, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक-अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) और फेस प्रमाणीकरण प्रदान करता है।
- अक्तूबर, 2023 तक 130.99 करोड़ आधार जारी किए जा चुके हैं। वयस्कों के लिए सेचुरेशन स्तर मई 2014 में 61.9% की तुलना में अब 100% के करीब पहुंच गया है।
- आधार का उपयोग करने वाली विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियाँ यथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) और भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) का विकसित किया गया है और बैंकिंग प्लेटफार्मों का उपयोग करके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसने देश में वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने में बड़ा सहयोग किया है।
- संचयी आधार प्रमाणीकरण लेनदेन 2014-15 में 40.70 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 10.97 हजार करोड़ हो गए हैं।
- लाइवनेस डिटेक्शन फीचर्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित फेस ऑथेंटिकेशन मॉडेलिटी की शुरुआत दिनांक 15.10.2021 को की गई और 16 अलग-अलग संस्थाओं को फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
- विभिन्न स्कीम जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, छात्रवृत्ति और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सब्सिडी को सेवा के लक्षित वितरण के लिए आधार के साथ एकीकृत किया गया है।
- आधार ने सरकार को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचने के योग्य बनाया ताकि सरकार लोगों के खातों में सीधे तौर पर लाभ और सब्सिडी दे सके जिससे भ्रष्टाचार, विचलन और लीकेज पर अंकुश लगा है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीमों के लिए अक्तूबर 2023 तक केंद्र सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आधार का उपयोग करने के लिए 1300 से अधिक सरकारी स्कीमों को अधिसूचित किया गया है।

II. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

(i) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मंच (एनएसपी)

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मंच का उद्देश्य देश भर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों को लागू करने के लिए साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। 12 मंत्रालयों/विभागों और 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कुल 140 स्कीम एनएसपी में शामिल हैं।
- वर्ष 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान डीबीटी मोड के माध्यम से लगभग 6.11 करोड़ लाभार्थियों को 28,134.99 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि संवितरित की गई है।

(ii) डिजिलॉकर

डिजिलॉकर भौतिक दस्तावेजों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरा है। 223.64 मिलियन से अधिक प्रयोक्ता पंजीकृत हैं और डिजिलॉकर पर 6.28 बिलियन दस्तावेज जारी किए गए हैं।

(iii) कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (कोविन)

कोविन ने टीकाकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने और लाभार्थियों को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1.11 बिलियन लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और कोविन पर टीकाकरण की 2.21 बिलियन वैकसीन दर्ज हुई है।

III. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के तहत ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 7.26 करोड़ उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 6.27 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से इस स्कीम के तहत 4.68 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र दिया गया है।

भारत अब दुनिया के अग्रणी 5जी इकोसिस्टम में से एक है। बेहतर कवरेज के परिणामस्वरूप सेवाओं की बेहतर प्रदायगी, डिजिटल वित्तीय समावेशन और नागरिकों का सशक्तिकरण होता है। भारत इस प्रक्रिया में अपने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक देश के रूप में उभरा है।

****